सिंचाई की सुविधाएँ

CC-0 Courtesy Shri K.S Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

सिंचाई की सुविधाएं

सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

किसानों के प्रति

आप की सबसे बड़ी जरूरत सिंचाई का भरपूर इन्तजाम है, क्योंकि आप किसान हैं। सिंचाई पर ही आप की पैदावार निर्भर करती है। अच्छी पैदावार से ही आपकी हालत सुधर सकती है— और आपकी खुशहाली से ही यह प्रदेश खुशहाल होगा, क्योंकि यह किसानों का ही प्रदेश है। इसलिए आपकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में सिंचाई-सुविधाओं के विस्तार की पूरी-पूरी कोशिश की। उसके इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आज ११८.२३ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधायें मिल चुकी हैं और अगले पांच वर्षों में अर्थात् तीसरी योजना के समाप्त होते-होते १४४.८४ लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचन-सुविधाएं उपलब्ध हो जायंगी।

इसके अतिरिक्त सरकार की सहायता से आपने भी सिंचाई-सुविधाओं का विस्तार किया है। आइये, देखें इन दस वर्षों में कितना काम हुआ और आगे हमें क्या करना है।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

सिंचाई का विस्तार

हमारी दो पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और तीसरी योजना के कामों को पूरा होते देखने के लिए प्रदेश का जन-जन उत्सुक है । सरकार द्वारा आयोजित विकास कार्यों को सफल करने में मदद देना हर देशवासी का पवित्र कर्त्तव्य है, क्योंकि उसकी तथा उसके आगे आने वाली पीढ़ी की सुख-सुविधा इन योजनाओं की सफलता पर ही निर्भर है । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाली जनता की आर्थिक दशा में एक ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे कि हमारा प्रदेश सुखी, समृद्ध एवं आत्म-निर्भर बन सके और समाजवादी ढांचे के समाज की रचना का हमारा स्वप्न पूरा हो सके ।

इसी बात को दृष्टि में रखकर पिछले दस वर्षों में ऐसे अनेक काम किये गये हैं जिससे गांवों में रहने वाले किसानों के खेतों की पैदावार बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े और उनका एवं उनकी संतानों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। खेती की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में किये गये अन्य अनेक कामों का उल्लेख हम यहां न करके सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार पर एक नजर डालेंगे ।

दस वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कुल ७६ लाख ९६ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएँ थीं, परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर ११८.२३ लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा हो गयी । सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि उनसे प्रदेश के सभी क्षेत्रों को लाभ पहुंचे । इसका फल यह हुआ है कि इन दस वर्षों में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ११.६ लाख एकड़, पश्चिमी क्षेत्र में ५७.६२ लाख एकड़, पूर्वी क्षेत्र में २८.३५ लाख एकड़, केन्द्रीय क्षेत्र में २०.० लाख एकड़ और बुन्देलखंड क्षेत्र में ११.०७ लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो गयी है ।

आप लोग किसान हैं इसलिये आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि अगर फसल के समय पर आवश्यकता के अनुसार पानी मिल जाय तो पैदावार पर क्या असर पड़ेगा । इन दस वर्षों में सरकार ने सिंचाई के साधनों का जो विस्तार किया है उनसे हमारे प्रदेश की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है, इसका अन्दाजा हर किसान आंक सकता है । पैदावार बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ी है और वे अधिक सुख-

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

मय जीवन की व्यवस्था कर सके हैं। जनता की सरकार ने सिंचाई-साधनों का विस्तार करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वह है सिंचाई-साधनों सम्बन्धी नीति में परिवर्तन। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी जमाने में भी कुछ नहरों का निर्माण किया गया था परन्तु उस समय इसका उद्देश्य जनता का हित न होकर सरकार के खजाने की वृद्धि करना था। सिंचाई के सिलसिले में जो निर्माण कार्य किये जाते थे उनकी लागत मय सूद-ब्याज और लाभ सहित जनता से प्राप्त की जाती थी। अब सिंचाई-साधनों से लाभ उठाना सरकार की नीति नहीं है।

इतना सब होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में सिंचाई-सुविधायें पर्याप्त हो गयी हैं, परन्तु दस वर्षों की अवधि में इससे अधिक किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। इसके लिए धन तथा निर्माण सामग्री की जरूरत तो होती ही है। साथ ही यह निर्माण-कार्य कहां और किस प्रकार किये जायं कि अधिक से अधिक लाभदायक हों, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी होता है। सिंचाई के छोटे साधन जैसे कुओं-तालावों का निर्माण, नलकूप लगाना आदि के सम्बन्ध में तो अधिक कठिनाई नहीं होती। ऐसे काम तो यदि किसान चाहें तो स्वयं कर सकते हैं। इसलिए पिछले दस वर्षों में सरकार ने सिंचाई के छोटे साधनों की व्यवस्था करने के लिए धन और प्राविधिक परामर्श देने की भरपूर व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप बहुत से किसानों ने अपने-अपने गांवों में अनेक ऐसे साधनों का निर्माण किया।

लेकिन सिंचाई की भरपूर व्यवस्था केवल इन्हीं साधनों से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए बड़े-बड़े बांधों और नहरों का निर्माण करना पड़ता है। नलकूपों से भी पानी निकालने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। इसलिए बिजली की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ती है। इस प्रकार सिंचाई के साधनों के साथ-साथ बिजली पैदा करने के लिए बिजलीघरों का भी निर्माण करना पड़ता है। सरकार ने पिछले दस वर्षों में बहुत से बड़े-बड़े बांधों, जलाशयों और नहर प्रणालियों का निर्माण किया है। यहां पर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये कुछ प्रमुख निर्माण कार्यों का उल्लेख करना असंगत न होगा। इनमें से कुछ आपके ही क्षेत्र के होंगे जिससे पहुंचने वाले लाभ से आप परिचित होंगे।

पहली योजना

पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल, १९५१ से आरम्भ हुई। इसमें लगभग ९५ करोड़ ४४ लाख रुपये की लागत से सिंचाई की विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

की गयीं । इनके परिणामस्वरूप योजना के आरम्भ में जो सिंचित क्षेत्र ७६ लाख ९६ हजार एकड़ का था वह योजना के अन्त में बढ़कर ९६ लाख ७९ हजार एकड़ हो गया। इस प्रकार प्रथम योजना-काल में लगभग २० लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएँ मिलीं । इनमें से प्रायः ११ लाख एकड़ क्षेत्र को वृहत् और माध्यमिक योजनाओं तथा लगभग ९ लाख एकड़ को छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन सिंचाई-सुविधाएँ प्राप्त हुईं । इस तरह पहली योजना-अवधि के अन्त तक कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग १७ प्रतिशत को सिंचाई की सुविधाएँ मिल गयीं । पहली योजना की समाप्ति पर राज्य में नहरों की लम्बाई २३,०१२ मील और नलकूपों की संख्या ४,५१५ हो गयी ।

प्रथम योजना के अन्तर्गत जिन सिंचन कार्यों का निर्माण किया गया उनमें माताटीला बांध (प्रथम चरण), शारदा सागर (प्रथमचरण), रगवा बांध, चन्द्रप्रभा बांध, नौगढ़ बांध और अर्जुन बांध मुख्य हैं । इनके अतिरिक्त योजना-काल के पहले आरम्भ किये गये अधूरे कार्यों को भी पूरा किया गया ।

माताटीला बांध प्रथम योजना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है । इसका निर्माण कार्य १९५१–५२ में आरम्भ हुआ था । इससे न केवल हमारे राज्य को अपितु मध्य प्रदेश को भी लाभ पहुँचा । यह बाँध २,२०० फुट लम्बा और १२० फुट ऊंचा है । इस बांध से झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों की २,६४,५०० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएँ मिली हैं ।

शारदा सागर का निर्माण पीलीभीत जिले में हुआ है । इस योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत इस बांध में २.५६ लाख एकड़ फुट पानी एकत्र होगा । इससे मध्यवर्ती तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग १.७२ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । इस योजना से बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर जिलों को लाभ पहुँचेगा। साथ ही शारदा सागर में मत्स्य पालन का विकास भी किया जायेगा ।

रंगवा बांध केन की सहायक नदी बनने पर बनाया गया है । इसका निर्माण कार्य १९५० में आरम्भ किया गया और प्रथम योजनावधि की समाप्ति तक इसे पूरा कर लिया गया । यह बांध ९२ फुट ऊँचा और ६,००० फुट लम्बा है । इसके पानी से केन नहर प्रणाली को अतिरिक्त पानी मिल सकेगा, जिसे बांदा जिले की ९३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

चन्द्रप्रभा बांध वाराणसी जिले में है। यह एक बहुधंधी योजना है। इससे एक ओर तो ३० वर्गमील क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा होती है दूसरी ओर २४,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई भी होती है। पांच सौ फुट लम्बे और ६० फुट ऊंचे इस बांध में २५,००० घनफुट पानी संग्रह करने की क्षमता है।

नौगढ़ बांध वाराणसी जिले में करमनासा नदी पर बनाया गया है। इसमें ३५,००० लाख घनफुट पानी एकत्र होता है। इससे वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील और गाजीपुर जिले के जमानियां परगने की प्रायः ८०,००० एकड़ भूमि सींची जाती है। इस योजना का निर्माण १९५२-५३ से शुरू कर दूसरी आयोजना में पूरा किया गया।

अर्जुन बांध हमीरपुर जिले में चरखारी नगर के समीप बनाया गया है। इसके पानी से हमीरपुर जिले की २७,००० एकड़ भूमि सींची जाती है। इस योजना का समारम्भ मार्च, १९५२ में हुआ और दिसम्बर, १९५५ में अर्थात् तीन वर्ष के अन्दर ही सिंचाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

इनके अतिरिक्त पहली पंचवर्षीय योजना काल में अनेक छोटे-बड़े सिंचन कार्यों का निर्माण किया गया। विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण किया गया। शारदा नहर प्रणाली के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में नहरों का निर्माण किया गया और गंगा नहर की क्षमता बढ़ाई गयी। इस संदर्भ में टांडा और दोहरी-घाट पम्प नहरों का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा।

प्रथम आयोजना के अन्तर्गत जो सिंचाई निर्माण कार्य किये गये, उनसे नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमौली, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून के पर्वतीय जिलों की ७५ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधायें मिलीं। इसी प्रकार मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद और इटावा के पश्चिमी जिलों की ५३ लाख १८ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई-सुविधाएं प्राप्त हुईं।

राज्य के पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर जिलों की १५ लाख ८ हजार एकड़

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

भूमि को सिंचाई-सुविधाएं मिलीं। मध्यवर्ती क्षेत्र के कानपुर, फतेहपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के जिलों की १८ लाख ६१ हजार एकड़ भूमि और बुन्देलखंड डिवीजन के झांसी, हमीरपुर, जालौन और बांदा जिलों की ८ लाख ८५ हजार एकड़ भूमि के लिए राजकीय सिंचाई साधनों की व्यवस्था की गयी।

दूसरी योजना का परिणाम

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत ११ बड़ी और २३ छोटी योजनाएं कार्यान्वित की गयीं। इन पर ३८ करोड़ ८ लाख रुपये व्यय हुये और इनके द्वारा सिंचित क्षेत्र में प्रायः २१ लाख ४८ हजार एकड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार द्वितीय आयोजनावधि के अंत में ११८ लाख २३ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई-सुविधायें मिल गयीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पहले कृषि योग्य १७ प्रतिशत क्षेत्र को सिंचाई-सुविधाएं उपलब्ध हो पाई थीं वहां द्वितीय आयोजना में २०.७ प्रतिशत क्षेत्र को लाभ पहुंचने लगा। दस वर्ष की अवधि में ७९.९९ लाख एकड़ से बढ़ाकर ११८.२३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था कर लेना एक उल्लेखनीय कार्य है।

द्वितीय आयोजना काल में प्रथम आयोजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर बल दिया गया। इस श्रेणी के कार्यक्रमों में नौगढ़ बांध, शारदा सागर (प्रथम चरण), दोहरीघाट उदंचित नहर, टांडा उदंचित नहर, ऊपरी गंगा नहर की क्षमता में वृद्धि, पूर्वी यमुना और आगरा नहरों के पुनर्निर्माण की योजनाएं थीं।

पुरानी योजनाओं को पूरा करने के अलावा दूसरी योजना अवधि में कुछ नयी योजनाएं भी कार्यान्वित की गयी। इनमें से माताटीला बांध (द्वितीय चरण), रामगंगा नदी योजना, बाल्मीकि सरोवर, जिरगो जलाशय, नानक सागर, तुमरिया जलाशय, मेजा जलाशय, शारदा सागर (द्वितीय चरण), कुवानो उदंचित नहर और ऊपरी खजुरी जलाशय प्रमुख हैं।

माताटीला बांध (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत जलद्वारों की व्यवस्था करके इसकी क्षमता ४,००,००० घन फुट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इससे प्रायः ४ लाख १२ हजार ५ सौ एकड़ भूमि को सिंचाई-सुविधा मिलेगी। इसमें से २,५८,५०० एकड़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का और शेष मध्य प्रदेश का होगा। इसके अलावा बांध के नीचे की ओर ३०,००० किलोवाट प्रतिष्ठापित क्षमता

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

वाले एक बिजलीघर के बनाने की भी योजना है। इस योजना को तृतीय योजना काल में पूरा किया जायगा।

रामगंगा नदी योजना सिंचन और विद्युत् परियोजना है। इसके अधीन गढ़वाल जिले में कालागढ़ के निकट एक १,८३० फुट लम्बा और ४१२ फुट ऊँचा बाँध निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिससे १७·०५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त १,५०,००० किलोवाट क्षमता का एक बिजलीघर भी बनाया जायेगा। इस महती योजना के चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजनावधि में पूर्ण होने की आशा है।

वाल्मीकि सरोवर के अधीन १३,५४० लाख घनफुट जलसंचय की क्षमता वाले एक मिट्टी के बांध के निर्माण की व्यवस्था है। इससे बांदा जिले की १५,५०० एकड़ भूमि को सिंचन-सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

जिरगो जलाशय मिर्जापुर जिले में जिरगों नदी पर बनाया गया है, इससे गाजीपुर, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों की लगभग ६४,००० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इससे सिंचाई कार्य शुरू हो गया है।

नानकसागर योजना के अधीन देहुला नदी पर एक बांध और घोरा नदी पर दूसरा बांध बनेगा। नानकसागर जलाशय खटीमा रेलवे स्टेशन से लगभग ९ मील दूर है। नानकसागर जलाशय १२ मील ६ फर्लांग लम्बा होगा। इसके द्वारा १,३१,७२० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। आशा है कि यह योजना तीसरी आयोजना के पूर्वार्द्ध में ही पूरी हो जायगी।

तुमरिया जलाशय योजना के अधीन तुमरिया और ढेला नदियों के आरपार आठ मील से अधिक लम्बा मिट्टी का एक बांध डालने का प्रस्ताव है। यह नैनीताल जिले में होगा और इससे नैनीताल तथा मुरादाबाद जिलों की ४०,००० एकड़ भूमि को वार्षिक सिंचन-सुविधा प्राप्त होगी। इसको तृतीय आयोजना में पूरा किया जायगा।

मेजा जलाशय योजना के अन्तर्गत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाने का प्रस्ताव है। इससे इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों की ७०,९०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जायगी। इसके मुख्य बांध का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष (१९६१–६२) में प्रारम्भ होने जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत बनी कुछ नहरों को सिरसी बांध से पानी मिल रहा है।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

शारदा सागर योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण के बांध को १२ फुट ऊंचा करने और शारदा प्रणाली की ६०२ मील लम्बी नहरों के बनाने की व्यवस्था है। द्वितीय चरण में इसकी क्षमता १,३१,३३३.४ लाख घन फुट कर देने का लक्ष्य है। इस योजना के पूर्ण होने पर १,६५,२५० अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके तीसरे आयोजना काल पूर्ण ोने की आशा है।

बस्ती जिले की २१,२३० एकड़ भूमि को सिंचन सुविधाएं प्रदान करने के लिये कुवानों नदी का कठनैया नाला से १२० क्यूसेक्स जल उदंचन करने का विचार है। इसे आंशिक रूप से चालू किया गया है, इस योजना के समस्त कार्यों के १९६३ तक पूर्ण होने की आशा है।

मिर्जापुर जिले में खजुरी नदी पर एक ७,२६० फुट लम्बा और ८० फुट ऊंचा मिट्टी का बांध तथा ४३ लम्बी नहरों का निर्माण कर १८,००० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस बांध के पानी का सिंचाई के लिये उपयोग किया जा रहा है। आशा है इसका शेष सभी कार्य १९६२ तक पूरी हो जायगा।

हम पहले ही कह चुके हैं कि पिछले दस वर्षों में यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार हुआ है पर वह प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। तीसरी योजना में भी सिंचाई साधनों के विस्तार का विशेष ध्यान रखा गया है।

भावी कार्यक्रम

तीसरी योजना में सिंचाई कार्यक्रमों के लिये ७१.७१ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़-नियंत्रण कार्यों के लिये ५.७५ करोड़ रुपये खर्च किये जायंगे। इस धनराशि में से सिंचाई की बड़ी और माध्यमिक योजनाओं के लिये ५१.७१ करोड़ रुपये और लघु सिंचन योजनाओं के लिये २० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। तीसरी योजना के अंत में प्रदेश में सिंचित क्षेत्र ११८.२३ लाख एकड़ से बढ़कर अनुमानतः १४४ लाख ८४ हजार एकड़ हो जायगा। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि के २५.३ प्रतिशत को सिंचन सुविधाएं प्राप्त हो जायंगी।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

जिस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना की अपूर्ण चालू योजनाओं के कार्य को दूसरी योजना में प्राथमिकता दी गयी थी, उसी प्रकार तीसरी योजना में दूसरी योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम पहले हाथ में लिया गया। ये योजनाएं प्रायः वे बहुमुखी दीर्घकालिक योजनाएँ हैं, जो पहली योजना के उत्तरार्द्ध में आरम्भ होकर दूसरी योजना के पूरे समय कार्यान्वित होती रहीं और तीसरी योजनाकाल के आरम्भ होने तक पूरी नहीं हो पायी थीं। वास्तव में इन योजनाओं की रूपरेखा ही ऐसी निर्धारित की गयी थी कि इनका कार्य अलग-अलग चरण में पूरा किया जाय। इसका एक कारण तो इन योजनाओं में लगने वाला समय था और दूसरा सीमित वित्तीय साधन। इनमें रामगंगा नदी योजना, शारदा सागर (द्वितीय चरण), नानक सागर, तुमरिया जलाशय, पूर्वी जमुना नहर का पुनरोद्धार, आगरा नहर का पुनरोद्धार, सजा जलाशय, कुवानों उदंचित नहर, दोहरी घाट उदंचित नहर, टांडा उदंचित नहर, सिरसी जलाशय, अपर खजुरी जलाशय, माताटीला बाँध तथा वाल्मीकि (ओहन) सरोवर प्रमुख हैं। इनमें कुछ योजनाएँ १९६२ और अधिकांश १९६३ के अन्त तक पूरी हो जायेंगी। इनके तैयार हो जाने के बाद इन सिंचाई कार्यों से कुल २६, १६,५०० एकड़ भूमि को प्रमुख सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी।

पहले की अधूरी इन महत् और माध्यमिक योजनाओं को पूरा करने के साथ ही कुछ योजनाएं भी तैयार की गयी हैं। इनमें कुछ पुरानी योजनाओं के विस्तार की योजनाएं और कुछ सर्वथा नये सिरे से शुरू की जाने वाली योजनाएं हैं। पहली कोटि की योजनाओं में तुमरिया जलाशय का विस्तार, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में धान की सिंचाई हेतु नवीन नहरों का निर्माण, बेलन नहर पर नालियों का विस्तार, ललितपुर और केन नहरों पर ७८ मील लम्बी नालियों का निर्माण, धानापुर रजबहे पर ४० मील लम्बी नालियों का विस्तार, कबरई बांध पर १० मील लम्बी नालियों का विस्तार, अर्जुन बांध पर नहरों का विस्तार, गंडक नहर योजना जहांगीर गंज ब्रांच तथा ओहन नहर पर ५ मील लम्बी नालियां बनाने की योजनाएं पहले से ही निर्मित सिंचाई साधनों की क्षमता और उपयोगिता बढ़ाने के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत तैयार किये गये कार्यक्रमों से संबंधित हैं। इन कार्यों के पूरा हो जाने पर नैनीताल, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, बहराइच, झांसी,

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

बांदा, वाराणसी और हमीरपुर जिले की लगभग ७,९५,२०५ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को सुविधाएं मिल सकेंगी। नरोरा बांध के पुनरुद्धार का काम भी इसी योजना काल में किया जायगा। इस बांध का निर्माण लोअर गंगा नहर प्रणाली में जल-वितरण के लिये १८७५ में किया गया था, किन्तु यह बांध रामगंगा बांध में एकत्र जल को लोअर गंगा नहर में प्रवाहित करने योग्य नहीं है। इसलिये इसका पुनरुद्धार कार्य अगले वर्ष ही आरम्भ किया जायगा।

मौजूदा सिंचाई कार्यों के विस्तार, सुधार और पुनरुद्धार के अतिरिक्त तीसरी योजना के अधीन कुछ नयी योजनाएं भी बनायी गयी हैं। बौर जलाशय, पीली जलाशय, सरजू नदी योजना, मूसाखंड जलाशय, चितौर गढ़ जलाशय, चितिया जलाशय, पकरी जलाशय, तकिया जलाशय, पूर्वी बहुगुल जलाशय और दयोहारी ताल योजनाएं इसी कोटि की हैं। अतएव इनका संक्षिप्त परिचय दे देना अनुचित न होगा।

बौर जलाशय का निर्माण काशीपुर रेलवे लाइन बौर नदी को जहां पार करती है वहां से लगभग आठ मील ऊपर की ओर किया जायगा। इससे तराई व रामपुर नहरों में पानी की कमी पूरी हो सकेगी और रामपुर तथा नैनीताल जिलों की ३९,२९० एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पीली जलाशय का निर्माण पीली नदी पर किया जायगा। सरजू नदी योजना के अन्तर्गत नानपारा (बहराइच) से १० मील उत्तर-पश्चिम की ओर सरजू नदी पर एक बराज बनाने और उससे एक नहर निकालने का कार्यक्रम है, इसमें बहराइच, गोंडा और बस्ती जिलों की १२,२८,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा और लगभग ४,१८,५०० एकड़ की सालाना सिंचाई होगी। मूसाखंड जलाशय योजना के अधीन कर्मनाशा नदी पर ५१,६७० लाख घनफुट जल-संग्रह क्षमता का एक जलाशय बनाया जायगा, जिससे वाराणसी और गाजीपुर जिलों की ३८,२२४ एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा। चित्तौड़गढ़ जलाशय योजना गोंडा जिले की २०,९०० एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा देने के लिये बनायी गयी है। इसके अधीन राप्ती नदी पर १६,५०० लाख घन फुट जल-संग्रह क्षमता का एक जलाशय बनाया जायगा। चितिया जलाशय योजना राप्ती नदी की एक सहायक नदी पर एक जलाशय का निर्माण कर गोंडा जिले की ३,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिये बनायी गयी है। गोंडा जिले की

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

अन्य ३,५०० एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु दकरी जलाशय योजना तैयार की गयी है। इसके अधीन राप्ती नदी के सहायक सोहनी नाले पर ६,४०० लाख घनफुट क्षमता का एक जलाशय बनाया जायगा। तकिया जलाशय योजना के अधीन बहराइच जिले की ४,५४७ एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के निमित्त राप्ती नदी के सहायक सुकई तथा सोनपतरी नालों पर एक जलाशय बनाया जायगा। पूर्वी बहगुल जलाशय बहगुल नदी पर बनेगा। इससे नैनीताल जिले की ८,२०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी क्योलारी ताल योजना हमीरपुर जिले की ३,६१७ एकड़ दो आबे की सिंचाई के लिये बनायी गयी हैं। इसके अधीन ३,००० लाख घनफुट क्षमता का एक जलाशय क्योलारी नदी में बांध डालकर बनाया जायगा। ये सारी योजनाएं १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में आरम्भ कर दी जायेंगी।

नलकूपों का निर्माण

हम पहले ही देख चुके हैं कि तत्काल और कम लागत में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु छोटी सिंचाई योजनाओं का अपना अलग महत्व है। दूसरी योजना के अधीन १,५०० नलकूपों के निर्माण का जो कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसमें से केवल १,०२० नलकूप बनाये जा सके और शेष ४८० नलकूपों का निर्माण कार्य तीसरी योजना में पूरा करने के लिये छोड़ दिया गया था। यह कार्य १९६४–६५ के अंत तक पूरा हो जायगा और इससे ४,८७,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। राजकीय नलकूपों पर गूलों के निर्माण सम्बन्धी योजना के अधीन प्रत्येक नलकूप से १ मील पक्की और २ मील कच्ची गूलों के स्थान पर प्रत्येक नलकूप से २ मील पक्की और २ मील कच्ची गूलों के निर्माण का निश्चय किया गया। इसकी पूर्ति हो जाने पर १,४९,५०० एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। साथ ही सहकारी नलकूपों के राज्य द्वारा ले लिये जाने के फलस्वरूप १२४ सहकारी नलकूप राजकीय नलकूपों में बदल जायंगे। इनमें से ८० नलकूप सरकार द्वारा दूसरी योजनाकाल में लिये गये और शेष तीसरी योजना में ले लिये जायेंगे। इन पर गूलों का निर्माण हो जाने के बाद २,५०० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इसके अतिरिक्त माट शाखा पर ९० नलकूपों के निर्माण की योजना के अधीन माट शाखा हेड वर्क्स से २४ मील तक फैले क्षेत्र में ९० फीडर नलकूप बनाये जायेंगे। इनसे दुहरा लाभ होगा।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

एक तो इनसे जमीन को जलमग्न होने से बचाया जा सकेगा, दूसरे ४३,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी। साथ ही पूर्वी जिलों में २०० राजकीय नलकूपों का निर्माण आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बहराइच तथा गोरखपुर जिलों की ७६,६०० एकड़ जमीन सिंचाई के लिये किया जायगा। ये नलकूप बन चुके हैं, केवल छोटे-मोटे कार्य बाकी हैं जो अगले वर्ष पूरे हो जायेंगे।

अन्य छोटे सिंचाई-कार्य

नलकूपों के निर्माण की योजना के अतिरिक्त अन्य 'छोटी सिंचाई योजनाएं भी हैं, जिन्हें तीसरी योजना-अवधि में पूरा करना है। दक्षिण उत्तर प्रदेश में छोटे बांध तथा बंधियों का निर्माण करने की योजनाधीन मिर्जापुर जिले की दुधी क्षेत्र में बरवार्डीह, सुखरा तथा कोटा जलाशयों, झांसी जिले में ललितपुर नहर, नौगढ़ क्षेत्र में बंधियों, महोबा में सालारपुर और इलाहाबाद में बागला ताल का निर्माण किया जा रहा है। इनसे १५,८४५ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान हेतु छोटी योजनाओं के अधीन छोटी सिंचाई और जल-निकासी योजनाओं को पूरा करने का निश्चय किया गया। ये योजनाएं मुख्यतः पहाड़ी जिलों, बुंदेलखंड तथा पूर्वी जिले के लिये हैं। इनसे देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, फैजाबाद, गोरखपुर मिर्जापुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन, टिहरी-गढ़वाल, गोंडा, वाराणसी, बलिया तथा आजमगढ़ जिलों की ८०,७३० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। ४६,८०० एकड़ रबी के पलिहर की सिंचाई हेतु गंगा व यमुना नहरों से उपलब्ध होने वाले वर्षा के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के उद्देश्य से माटशाखा, अपर एवं लोअर आगरा नहरों और रबी पलेवा नहरों का निर्माण किया जायगा। गोनामऊ माइनर का निर्माण रायबरेली जिले की १,१०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये होगा। गिरगिटी सरोवर योजना के अधीन एक बांध डाई मील लम्बा बनाया जायगा, जिसके जलाशय की क्षमता ३,२०० लाख घन फुट होगी और इससे ८,२०० एकड़ भूमि सींची जायगी। श्रीनगर ताल योजना गोरखपुर जिले की २,००० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये बनायी गयी है। माँडा रजवहा योजना के अधीन इलाहाबाद जिले की ८,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हेतु

C-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

१८ मील लम्बी नहरें बनाने का निश्चय किया गया है। बिलहर रजवहे का पुनरुद्धार करने के लिये ३ मील ६ फर्लांग नयी नहरों का निर्माण किया जायगा, जिससे ६,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।

इनके अतिरिक्त तीसरी योजना के अधीन कुछ नयी योजनाएं भी निर्धारित की गयी हैं। इस प्रकार की पांच योजनाएं तैयार की गयी हैं। इन योजनाओं का थोड़ा बहुत विवरण यहां दे देना अनुचित न होगा। नलकूपों को बिजली देने की योजना के अधीन द्वितीय आयोजना के अपूर्ण नलकूपों में से १,०२० नलकूपों को बिजली देने की व्यवस्था ३०० लाख रुपये की लागत पर की जायगी। इसमें से ३० लाख रुपया १९६१–६२ में खर्च होगा।

छोटे जलाशय तथा ताल की भी एक योजना बनायी गयी है। इसके अधीन बिलहर बांध, सोनखेरा, पलेथा नहरों का पक्का करना, गढ़वाल भावर में २० मील लम्बी नहरों, तराई में ४० मील लम्बी नहरों, हिनौती बांध, कल्लूवाला बांध, गुल्लरिया ताल, बिरोना ताल, ढलवा दबोही ताल, तुन्दियारी ताल, स्योती ताल, गोमापुर जलाशय, बचखौवा जलाशय, गढ़ई चप्पाताल, कनेडा ताल, जमालपुरताल, भोजूवाला ताल, मागदेवा ताल, जसडिया ताल, नवलगढ़ जलाशय, मंगलपुर जलाशय, मोतीपुर जलाशय, जलजलवा जलाशय, पूरनपुर जलाशय, कोहरीपुर बांध और पंचपुर ताल का निर्माण करके इलाहाबाद, आगरा, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, मिर्जापुर, बिजनौर, बहराइच, बांदा, झांसी, गोंडा और बस्ती को ५०,२१३ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जायगी। इस कोटि की तीसरी परियोजना सरयां माइनर, मेजन माइनर, अंजर माइनर, बरसई माइनर, गंगा माइनर, कनोली माइनर और भटनमाल दूला माइनर के निर्माण द्वारा अल्प सिंचन सुविधाओं वाले देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल जिलों की २,९४२ एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जायगी। चौथी योजना दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बंधियों के निर्माण की है। इसके अधीन दक्षिणी उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी जिलों में छोटी बंधियों के निर्माण की व्यवस्था है। इनसे २३,४०० एकड़ की प्रतिवर्ष सिंचाई हो सकेगी। पांचवीं योजना जल-निकासी कार्यों से संबंधित है। इसके अधीन निर्माण-कार्य पूरे हो जाने पर २,५५,३९० एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

सिंचाई और बिजली की मिलीजुली योजनाएं

हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारी कई सिंचाई योजनाएं एकांगी नहीं है। इस प्रकार की योजनाओं में जल-विद्युत् और सिंचाई की सम्मिलित योजनाएं आती हैं। इनकी थोड़ी बहुत जानकारी किये बिना सिंचाई विकास की कहानी अधूरी रह जायगी। इनमें जहां एक ओर सिंचाई के लिये पानी मिलेगा, वहीं उद्योगों और नलकूपों को चलाने के लिए बिजली उपलब्ध होगी। अतएव ये योजनाएं अत्यधिक महत्व की हैं। इनमें रिहन्द बांध योजना और जमुना पन बिजली योजना पहले से चली आने वाली योजनाएं हैं। 'इन्हें तीसरी योजना अवधि में पूरा किया जायगा। इनसे सिंचाई के अतिरिक्त क्रमशः २,५०,००० किलोवाट और ५६,५०० किलोवाट बिजली मिलेगी। इन मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त तीसरी योजनावधि में सोन तथा रेणु नदी के संगम से पहले रेणु नदी पर ओवरा पन बिजली योजना, झांसी जिले में ओरछा तथा ढकुवां, रेणु नदी की तलहटी में सिगरौली वाष्प बिजलीघर तथा प्रदेश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की अन्य योजनाओं का समावेश किया गया है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर उत्तर प्रदेश में एक साथ उद्योग और कृषि विस्तार के लिये क्रमशः बिजली और सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी।

पिछले पृष्ठों में हमने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इसमें आपको यह ज्ञात होगा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक भाग में सिंचाई की इतनी अधिक सुविधा पैदा कर देने के लिये प्रयत्नशील है कि किसानों को अपनी फसलों के लिये पानी की कमी न पड़े और साथ ही उन्हें अतिरिक्त फसलें पैदा करने के लिये भी पानी मिल सके। ऐसा होने पर प्रदेश में खेती की उन्नति होगी, पैदावार बढ़ेगी, किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रदेश की खुशहाली बढ़ेगी।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी०-४६ जनरल (पब०)—१९६१—२,००,०००।

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri

नियोजन के १० वर्ष

देश के आर्थिक
और सामाजिक
विकास के अग्रदूत

राष्ट्र को संपन्न
और शक्तिशाली
बनाने के लिए

तीसरी
पंच-वर्षीय योजना
में योग दें

COVER PRINTED BY G. W. LAWRIE & Co., LUCKNOW.

CC-0.Courtesy Shri K.S.Parihar Librarian Government District Library Varanasi. Digitized by eGangotri